



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-17042026-271886
CG-KA-E-17042026-271886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]
No. 278]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2026/चैत्र 27, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2026/CHAITRA 27, 1948

केनरा बैंक
(मानव संसाधन विभाग)
अधिसूचना
बेंगलूरु, 17 अप्रैल, 2026

क्रमांक HRW PM 257 2026.— बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पढ़ी गई धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केनरा बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के पत्र संख्या 4/2/1/2022-IR, दिनांक 13 मार्च, 2024 के अनुसरण में किए गए या न किए गए कार्यों को छोड़कर, 1 नवंबर, 2022 से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक, केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों को केनरा बैंक (अधिकारियों) सेवा (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (जिसे इसके बाद उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 3 में, खंड (f) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(f) चिकित्सा सुविधाओं और अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी कर्मचारी के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है —

- (i) अधिकारी के पति/पत्नी;
- (ii) पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चे और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे सहित);
- (iii) पूरी तरह से आश्रित, शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग भाई या बहन, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो;
- (iv) विधवा पुत्रियाँ और आश्रित तलाकशुदा या अलग हुई पुत्रियाँ;
- (v) बहनें, जिनमें अविवाहित, तलाकशुदा, पति द्वारा छोड़ी गई, पति से अलग हुई या विधवा बहनें शामिल हैं; और
- (vi) माता-पिता, जो पूरी तरह से अधिकारी पर आश्रित हों:

बशर्ते कि शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में, उनकी आयु चाहे जो भी हो, उन्हें विवाह के बाद भी आश्रित ही माना जाएगा, बशर्ते कि वे आश्रित होने के लिए निर्धारित आय मानदंडों को पूरा करते हों।

स्पष्टीकरण 1.—“पूर्णतः आश्रित परिवार का सदस्य” का अर्थ परिवार का वह सदस्य होगा जिसकी मासिक आय 18,000/- रुपये से अधिक न हो; और यदि माता-पिता में से किसी एक की मासिक आय 18,000/- रुपये से अधिक है, या दोनों माता-पिता की मासिक आय का कुल योग 18,000/- रुपये से अधिक है, तो दोनों माता-पिता को अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना और अवकाश किराया रियायत के प्रयोजनों के लिए, सभी अधिकारियों के मामले में, आश्रित पिता, माता, ससुर और सास में से किन्हीं दो को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अधिकारी के पास यह विकल्प होगा कि वह एक कैलेंडर वर्ष में एक बार, इन आश्रितों में से किसी एक या दोनों को बदल सके।

स्पष्टीकरण 3.— यह परिभाषा 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी और कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए, चिकित्सा बीमा योजना के प्रयोजन हेतु, आश्रितों के लिए संशोधित मासिक आय मानदंड 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी होंगे।

3. उक्त विनियमनों के विनियमन 4 में,—

- (a) उप-विनियम (7) के स्पष्टीकरण को छोड़ दिया जाएगा।
- (b) उप-विनियम (9) और (10) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(9) 1 नवंबर, 2022 से, प्रत्येक ग्रेड के सामने निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

(a) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड

वेतनमान VIII = रु. 253000 - 9000/4 - 289000

वेतनमान VII = रु. 156500 - 4340/4 - 173860

वेतनमान VI = रु. 140500 - 4000/4 - 156500

(b) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान V = रु. 120940 - 3360/2 - 127660 - 3680/2 - 135020

वेतनमान IV = रु. 102300 - 2980/4 - 114220 - 3360/2 - 120940

(c) मध्य प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान III = रु. 85920 - 2680/5 - 99320 - 2980/2 - 105280

वेतनमान II = रु. 64820 - 2340/1 - 67160 - 2680/10 - 93960

(d) जूनियर प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान I = रु. 48480 - 2000/7 - 62480 - 2340/2 - 67160 - 2680/7 - 85920.

स्पष्टीकरण— प्रत्येक अधिकारी, जो 31 अक्टूबर, 2022 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित है, उसे 1 नवंबर, 2022 को इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में चरण-दर-चरण आधार पर, अर्थात् संबंधित वेतनमानों में पहले चरण से आगे के संगत चरणों पर समायोजित किया जाएगा; और वेतन-वृद्धियां (इंक्रिमेंट्स) सामान्य रूप से वर्षगांठ की तारीख पर ही मिलेंगी, सिवाय उन मामलों के जहां अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

(10) उप-विनियमों (1) से (9) में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी ग्रेडों में अधिकारी कार्यरत होना आवश्यक है।

(11) 1 नवंबर, 2012 से, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएँगे:

वेतनमान I - III - मूल वेतन का 7.75 प्रतिशत, साथ ही उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV - V - मूल वेतन का 10 प्रतिशत, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI - VII - मूल वेतन का 11 प्रतिशत, साथ ही उस पर लागू महंगाई भत्ता।

(12) 1 नवंबर, 2017 से, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएँगे:

वेतनमान I - III - मूल वेतन का 16.40 प्रतिशत, साथ ही उस पर लागू महंगाई भत्ता।

वेतनमान IV - V - मूल वेतन का 19 प्रतिशत, साथ ही उस पर लागू महंगाई भत्ता।

वेतनमान VI - VIII - मूल वेतन का 20 प्रतिशत, साथ ही उस पर लागू महंगाई भत्ता:

बशर्ते कि वेतनमान-VIII का कोई अधिकारी 31 मार्च, 2020 से विशेष भत्ते के लिए पात्र होगा।

(13) 1 नवंबर, 2022 से, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएँगे:

वेतनमान I - मूल वेतन का 26.50 प्रतिशत, साथ ही उस पर लागू महंगाई भत्ता।

वेतनमान II - III - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत, साथ ही उस पर लागू महंगाई भत्ता।

वेतनमान IV-V - मूल वेतन का 30.50 प्रतिशत, साथ ही उस पर लागू महंगाई भत्ता।

वेतनमान VI-VII - मूल वेतन का 31.50 प्रतिशत, साथ ही उस पर लागू महंगाई भत्ता।

वेतनमान VIII - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता।

नोट: उप-विनियम (11) से (13) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता, और उस पर लागू महंगाई भत्ता, अधिवार्षिकी लाभों—जैसे कि पेंशन (जिसमें परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन योजना शामिल है), भविष्य निधि और ग्रेच्युटी—की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

4. उक्त विनियमन के विनियमन 5 में,—

(a) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (9) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 नवंबर, 2022 से, वेतन-वृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:—

- (a) विनियम 4 के उप-विनियम (9) में निर्धारित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतन-वृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, वार्षिक आधार पर अर्जित होंगी और उस महीने के पहले दिन प्रदान की जाएंगी जिस दिन वे देय होती हैं;
- (b) अपने-अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I के अधिकारियों को, नीचे खंड (c) में निर्दिष्ट अनुसार, केवल अगले उच्चतर वेतनमान में और वेतन-वृद्धियाँ (जिसमें स्थिर-वृद्धि भी शामिल है) प्रदान की जाएँगी; बशर्ते कि वे दक्षता-सीमा को पार कर लें।
- (c) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I के अधिकारी, जो खंड (b) के तहत उच्च वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II के वेतनमान में चले गए हैं, वे प्रत्येक दो साल की सेवा पूरी करने पर सात स्थिर वेतन वृद्धि (स्टैग्रेशन इंक्रीमेंट्स) के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो 2680/- रुपये प्रत्येक और अगले पांच 2980/- रुपये प्रत्येक होंगे:

बशर्ते कि एक अधिकारी पांचवें स्थिर वेतन वृद्धि के जारी होने के दो साल बाद, या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, छठे स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि एक अधिकारी पांचवें स्थिर वेतन वृद्धि जारी होने के चार साल बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

- (d) मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II के वे अधिकारी, जो खंड (b) के अनुसार मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III के वेतनमान में चले गए हैं, और जो उच्च वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँच चुके हैं, वे अपनी सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए 2980/- रुपये के सात स्थिर वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

बशर्ते कि कोई अधिकारी पाँचवें स्थिर वेतन वृद्धि के जारी होने के दो वर्ष बाद, या 1 नवंबर, 2022- इनमें से जो भी बाद में हो—छठे स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

इसके अलावा, कोई अधिकारी पाँचवीं स्थिर वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद, या 1 नवंबर, 2022 को—इनमें से जो भी बाद में हो—सातवीं स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

- (e) मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III के स्थायी अधिकारियों, अर्थात् मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत होने वाले अधिकारियों को, वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद पूर्ण की गई सेवा के प्रत्येक दो वर्ष के लिए आठ स्थिर वेतनवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिनमें से पहली चार स्थिर वेतनवृद्धियां 2980 रुपये प्रत्येक की होंगी और अगली चार स्थिर वेतन वृद्धियां 3360 रुपये प्रत्येक की होंगी।

बशर्ते कि कोई अधिकारी छठी वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

इसके अलावा, कोई अधिकारी छठी वेतन वृद्धि जारी होने के चार साल बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, आठवीं वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

- (f) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद प्रत्येक दो पूर्ण सेवा वर्षों के लिए पांच स्थिर वेतनवृद्धि के पात्र होंगे, जिनमें से पहली स्थिर वेतनवृद्धि 3360

रुपये की होगी और अगली चार स्थिर वेतनवृद्धियां 3680 रुपये की होंगी।

बशर्ते कि कोई अधिकारी दूसरी वेतन वृद्धि जारी होने के दो साल बाद या 1 नवंबर, 2022, इनमें से जो भी बाद में हो, तीसरी वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

इसके अलावा, कोई अधिकारी दूसरी वेतन वृद्धि जारी होने के चार साल बाद या 1 नवंबर, 2022, इनमें से जो भी बाद में हो, चौथी वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

इसके अलावा, कोई अधिकारी दूसरी वेतन वृद्धि जारी होने के छह साल बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, पांचवीं वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

- (g) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान V के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद, प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों की सेवा के लिए 4000 रुपये की चार स्थिर वेतनवृद्धि के पात्र होंगे।

बशर्ते कि कोई अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, दूसरी वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

इसके अलावा, अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के छह वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, उस तारीख से तीसरी स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

इसके अलावा, कोई अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के आठ वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, चौथी वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

- (h) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड वेतनमान VI के अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के बाद प्रत्येक दो पूर्ण सेवा वर्षों के लिए तीन स्थिर वेतनवृद्धि के पात्र होंगे, जिनमें से पहली दो स्थिर वेतनवृद्धि 4000 रुपये प्रत्येक की होंगी और तीसरी स्थिर वेतनवृद्धि 4340 रुपये की होगी।

बशर्ते कि जो अधिकारी पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, के बाद 4000/- रुपये की पहली स्थिर वेतनवृद्धि का पात्र होगा:

इसके अलावा, जो अधिकारी पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के चार साल बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, उस तारीख से 4000/- रुपये की दूसरी वेतन वृद्धि का हकदार होगा।

इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि जो अधिकारी पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के छह साल बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, के बाद 4340/- रुपये की तीसरी स्थिर वेतनवृद्धि का पात्र होगा;

- (i) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड वेतनमान VII के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद, प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों की सेवा के लिए 4340/- रुपये की तीन स्थिर वेतनवृद्धि के पात्र होंगे।

बशर्ते कि जो अधिकारी पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो साल बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, को पहली स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

इसके अलावा, जो अधिकारी पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के चार साल बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, उस तारीख से दूसरी वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि जो अधिकारी पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के छह साल बाद या 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, के बाद तीसरी स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

नोट: इस उप-विनियम के खंड (c) से (i) में उल्लिखित वेतन वृद्धि, ऐसे किसी अधिकारी को अनुमत नहीं होगी जो पदोन्नति का प्रस्ताव दिए जाने पर उसे अस्वीकार कर देता है।

स्पष्टीकरण — इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, अगले उच्चतर वेतनमान में वेतन-वृद्धि देना पदोन्नति नहीं माना जाएगा, और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियाँ, कर्तव्य और उत्तरदायित्व वैसे ही बने रहेंगे, मानो वे मूल पदों पर ही हों।

(b) उप-विनियम (2) में,—

(i) स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे, अर्थात्: —

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2022 से, जो अधिकारी 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' परीक्षा (सीएआईआईबी) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' परीक्षा का भाग II (सीएआईआईबी-II) पूरा कर लेंगे, वे अपने वेतनमान में दो वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे; यह उन एक वेतन-वृद्धि के अतिरिक्त होगी जो उन्हें 'जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' परीक्षा (जेएआईआईबी) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' परीक्षा का भाग I (सीएआईआईबी-I) पूरा करने पर मिलती है:

इसके अलावा, वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 2022 को बैंक की सेवा में थे और जिन्होंने पहले ही 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' (सीएआईआईबी) या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' के भाग II (सीएआईआईबी-II) को पूरा कर लिया है, वे 1 नवंबर, 2022 से, या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' (सीएआईआईबी) अथवा 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' के भाग II (सीएआईआईबी-II) को उत्तीर्ण करने की तिथि से—इन दोनों में से जो भी तिथि बाद की हो—दूसरे अतिरिक्त वेतन-वृद्धि के लिए पात्र होंगे।

इसके अलावा, यह भी शर्त है कि जिस मामले में कोई अधिकारी, 8 मार्च, 2024 तक, पहले ही 'जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' (जेएआईआईबी) ['सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' का भाग I (सीएआईआईबी-I)] या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' (सीएआईआईबी) ['सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' का भाग II (सीएआईआईबी-II)] की योग्यता

प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करता है—और ऐसा उसने वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के बाद [जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) के मामले में], या वेतनमान की अधिकतम सीमा से एक चरण कम वाले स्तर तक पहुँचने के बाद [सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) के मामले में] किया है—और उसे ऐसी योग्यता प्राप्त करने के आधार पर मिलने वाला वेतन-वृद्धि नहीं मिला है (क्योंकि उस समय उन कर्मचारियों के वेतनमान में देने के लिए कोई वेतन-वृद्धि उपलब्ध नहीं थी), तो ऐसे मामलों में 'स्थिर वेतन-वृद्धि' को एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, पहले दिया जा सकता है।

(ii) व्याख्या में, खंड (h) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) 1 नवंबर, 2022 से, अन्य बातों के समान रहने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा को निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार संशोधित किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

जिन्होंने 'जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' (भाग-I) पास किया है।	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक साल बाद, ₹1370/- प्रति माह।
जिन्होंने 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' के दोनों भाग पास किए हैं।	(a) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद, ₹1370/- प्रति माह; (b) अधिकतम वेतनमान पर पहुँचने के दो साल बाद ₹3425/- प्रति माह; और (c) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के तीन वर्ष बाद, ₹5,480/- प्रति माह।

बशर्ते कि कोई अधिकारी-कर्मचारी, जो वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के बाद 'जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' या 'सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स' (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) की योग्यताएँ प्राप्त करता है, उसे ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि से 'व्यावसायिक योग्यता वेतन' की पहली किस्त प्रदान की जाएगी; और 'व्यावसायिक योग्यता वेतन' की बाद की किस्तों का भुगतान, 'व्यावसायिक योग्यता वेतन' की पहली किस्त के भुगतान की तिथि के संदर्भ में किया जाएगा:

आगे यह भी प्रावधान किया जाता है कि 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद से, स्केल VIII में काम कर रहे किसी भी अधिकारी को कोई व्यावसायिक योग्यता वेतन देय नहीं होगा।

(iii) टिप्पणी में, खंड (v) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, अर्थात्:

“(vi) वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 2022 को बैंक की सेवाओं में थे और जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स (जेएआईआईबी) [सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स का भाग I (सीएआईआईबी-I)] या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स (सीएआईआईबी) [सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़

बैंकर्स का भाग II (सीएआईआईबी-II)] पूर्ण कर लिया है और व्यावसायिक योग्यता वेतन -II प्राप्त कर रहे हैं, वे व्यावसायिक योग्यता वेतन -II जारी होने के एक वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022 से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक योग्यता वेतन -III के लिए पात्र होंगे।

(vii) वे अधिकारी जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (जेएआईआईबी) [सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का भाग I (सीएआईआईबी-I)] या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) [सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का भाग II (सीएआईआईबी-II)] पूर्ण कर लिया है और 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले वेतनमान में अधिकतम स्तर पर पहुंच गए हैं तथा 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले पहली स्थिर वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं की है, वे 1 नवंबर, 2022 से व्यावसायिक योग्यता वेतन-I के लिए पात्र होंगे तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन की अगली किस्त का निर्गमन इस खंड के अंतर्गत व्यावसायिक योग्यता वेतन-I के निर्गमन की तिथि के संदर्भ में होगा।

(c) उप-विनियम (3) के तहत,—

- (i) खंड (g) के बाद का नोट हटा दिया जाएगा;
- (ii) खंड (h) के स्थान पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) 1 नवंबर, 2022 से, अन्य बातों के समान रहने पर, मकान किराया भत्ता सहित निश्चित व्यक्तिगत वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा:

तालिका

वृद्धि घटक (रु.)	1 नवंबर, 2022 को वेतन वृद्धि के घटकों पर महंगाई भत्ता (रु.)	कुल निश्चित व्यक्तिगत वेतन, जहाँ बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया हो (रु.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669.

नोट:

- (i) इस उप-विनियम के खंड (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) और (i) में दी गई तालिका के कॉलम (3) के अंतर्गत दर्शाया गया 'निश्चित व्यक्तिगत भत्ता' या 'निश्चित व्यक्तिगत वेतन' उन अधिकारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है।
- (ii) मकान किराया भत्ता के लिए पात्र अधिकारियों के लिए निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन, खंड (i) के अंतर्गत तालिका के कॉलम (1) और (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट कुल राशि और संबंधित अधिकारी द्वारा नियम 4 के उप-नियमों (2), (3), (4),

- (5), (6), (7), (8) और (9) में निर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि अर्जित होने पर प्राप्त मकान किराया भत्ता होगा;
- (iii) केवल वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में हैं, वे अपने द्वारा निर्धारित अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष बाद निश्चित व्यक्तिगत वेतन के पात्र होंगे।
- (iv) 1 नवंबर, 1999 से, निश्चित व्यक्तिगत वेतन भुगतान के कारण उप-नियम (2) के स्पष्टीकरण के खंड (c) में उल्लिखित व्यावसायिक योग्यता वेतन की रिहाई की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा:
 बशर्ते कि यदि व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पूर्ववर्ती प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी होने वाली है, तो वह इस तिथि से अधिकारी को जारी की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।
- (v) निश्चित व्यक्तिगत भत्ते या निश्चित व्यक्तिगत वेतन के वृद्धि घटक को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- (vi) वह अधिकारी जिसने ऊपर खंड (a) के अनुसार अग्रिम वेतन-वृद्धि अर्जित की है, वह इस उप-विनियम के खंड (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) और (i) में उल्लिखित 'निश्चित व्यक्तिगत भत्ते' या 'निश्चित व्यक्तिगत वेतन' की राशि, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद प्राप्त करेगा।

5. उक्त विनियमनों के विनियमन 21 में,—

- (a) उप-विनियम (6) का स्पष्टीकरण हटा दिया जाएगा।
 (b) उप-विनियम (7) के उपरांत, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(8) 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद से,—

- (a) महंगाई भत्ता, सूचकांक के प्रति प्रतिशत बिंदु पर वेतन के 1 प्रतिशत की दर से देय होगा।
- (b) औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के तिमाही औसत में 123.03 अंकों से अधिक की वृद्धि या कमी के प्रत्येक परिवर्तन के लिए उपर्युक्त तरीके से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा (आधार 2016 = 100)। सीपीआई 2016 के प्रत्येक दूसरे दशमलव स्थान में 123.03 अंकों से अधिक के परिवर्तन के लिए वेतन पर महंगाई भत्ते में 0.01% का परिवर्तन होगा।
- (c) महंगाई भत्ता दर में परिवर्तन की घोषणा तिमाही आधार पर 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर और 1 फरवरी को निम्नलिखित आधारों पर की जाएगी, अर्थात्:—

महंगाई भत्ते जारी होने की तिथि	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बिंदुओं का मासिक तिमाही औसत	इन महीनों के लिए लागू
1 मई	जनवरी, फरवरी और मार्च	मई, जून और जुलाई
1 अगस्त	अप्रैल, मई और जून	अगस्त, सितंबर और अक्टूबर

1 नवंबर	जुलाई, अगस्त और सितंबर	नवंबर, दिसंबर और जनवरी
1 फरवरी	अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर	फरवरी, मार्च और अप्रैल;

(d) महंगाई भत्ते पर कोई सीमा नहीं होगी।

(e) त्रैमासिक औसत की गणना करते समय, केवल पहले दो दशमलव अंकों पर ही विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियमन के प्रयोजन के लिए,-

(a) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" का अर्थ होगा मूल वेतन, जिसमें स्थिर वेतन वृद्धि तथा विशेष भत्ता शामिल हो;

(b) नियम 5 के उप-नियम (2) के स्पष्टीकरण के खंड (c), (d), (e), (f), (g), (h) और (i) में निर्दिष्ट 'व्यावसायिक योग्यता भत्ता' या 'व्यावसायिक योग्यता वेतन', 'महंगाई भत्ते' के लिए पात्र होगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से,—

(a) बैंक द्वारा आवासीय सुविधा दिए जाने पर, अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन का 0.35% या आवास का मानक किराया, जो भी कम होगा, वसूल किया जाएगा।

(b) जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वहाँ वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा, अर्थात्:—

तालिका

क्र.सं.	कार्यस्थल	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)	(3)
1.	समूह 'ए' में शामिल प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर और परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 10.0%
2.	क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह B तथा गोवा राज्य में स्थित परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 9.0%
3.	अन्य स्थान	वेतन का 8.0%

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता उसके द्वारा आवासीय आवास के लिए भुगतान किए गए वास्तविक किराए के बराबर होगा, जो वेतनमान के प्रथम चरण में उसके वेतन के 0.35 प्रतिशत से अधिक होगा, और यह अधिकतम 150 प्रतिशत तक होगा, जो कि उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ता होगा।

नोट:- अधिकारियों द्वारा अपने स्वामित्व वाले आवास की लागत से संबंधित मकान किराया भत्ता के दावों को भी पहले की तरह मकान किराया भत्ता के 150 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) 1 नवंबर, 2022 से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित स्थान पर सेवारत है, तो उस स्थान के लिए कॉलम (3) में उल्लिखित दर पर शहर क्षतिपूर्ति भत्ता देय होगा।

तालिका		
क्र.सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्र 1 व उससे ऊपर के स्थान, और गोवा राज्य	₹2300/- प्रति माह
2.	जिन स्थानों की जनसंख्या पाँच लाख या उससे अधिक है, तथा राज्यों की राजधानियाँ और चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर।	₹1900/- प्रति माह

(2) 1 नवंबर, 2022 से, विशेष क्षेत्र भत्तों की दरें इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगी।

बशर्ते कि, जहाँ अनुसूची के कॉलम (1) में बताए गए किसी भी स्थान पर, उप-विनियम (10) के तहत दिया जाने वाला 'पहाड़ी और ईंधन भत्ता' भी देय है, तो अधिकारी इन दोनों भत्तों में से केवल अधिक राशि वाले भत्ते को ही प्राप्त करने का पात्र होगा, दोनों को नहीं।

इसके अलावा, यदि दोनों भत्तों में से अधिक भत्ता, 31 दिसंबर, 1989 को अधिकारी द्वारा प्राप्त विशेष भत्ता और पहाड़ी एवं ईंधन भत्ते के कुल योग से कम है, तो यह अंतर व्यक्तिगत भत्ते के रूप में तब तक संरक्षित रहेगा जब तक अधिकारी उस स्थान पर रहता है।

(3) 1 नवंबर, 2017 से, यदि कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी में आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत है, तो वह क्षेत्र के समूह ए या समूह बी के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः 600/- रुपये प्रति माह या 525/- रुपये प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता के लिए पात्र होगा।

(4) 1 अप्रैल, 2024 से, यदि किसी अधिकारी का तबादला शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, और यदि उसके एक या अधिक बच्चे पहले वाले स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह उस तारीख से, जिस दिन वह दूसरे स्थान पर कार्यभार ग्रहण करता है, शैक्षणिक वर्ष के अंत तक, प्रति बच्चा 2500/- रुपये प्रति माह के 'मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते' का हकदार होगा; यह भत्ता अधिकतम दो बच्चों तक के लिए मान्य होगा।

बशर्ते कि यदि सभी बच्चे उस पूर्व स्थान पर पढ़ाई करना बंद कर दें, तो ऐसा भत्ता बंद हो जाएगा।

(5) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़े पारिश्रमिक प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, 7.75 प्रतिशत की दर से

प्रतिनियुक्ति भत्ता (अधिकतम 7500/- रुपये प्रति माह) और ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर मिलते।

बशर्ते कि, जहाँ ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है, या किसी ऐसे प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो बैंक के स्वामित्व में नहीं है—जहाँ वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले पदस्थ था—तो उसे उसके वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 3750/- रुपये प्रति माह होगी।

बशर्ते कि, यदि किसी अधिकारी को उसी नगरपालिका सीमा या शहरी समूह के भीतर किसी अन्य कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है (मेट्रो या प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहरों में), और यदि ऐसी प्रतिनियुक्ति की दूरी मूल शाखा या कार्यालय से बीस किलोमीटर या उससे अधिक है, तो वह विनियम 41 के उप-विनियम (4) के अनुसार 'ठहरने के भत्ते' के लिए पात्र होगा।

- (6) 1 अप्रैल, 2024 से और उसके बाद, यदि किसी अधिकारी को किसी उच्च वेतनमान वाले पद पर, एक बार में लगातार कम से कम चार दिनों की अवधि के लिए, या किसी कैलेंडर माह के दौरान कुल मिलाकर चार दिनों के लिए कार्यवाहक के रूप में कार्य करना आवश्यक हो, तो उसे उसके मूल वेतन का 15 प्रतिशत के बराबर 'कार्यवाहक भत्ता' प्राप्त होगा। यह भत्ता उस अवधि के अनुपात में दिया जाएगा जिसके लिए उसने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है, और यह कार्यवाहक भत्ता केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनों के लिए ही 'वेतन' के रूप में माना जाएगा।

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अंतर्गत पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप ही उच्च वेतनमान में कार्यवाहक के रूप में नियुक्त होता है, तो वह वर्गीकरण की समीक्षा के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यवाहक भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा।

- (7) 1 अप्रैल, 2024 से, एक अधिकारी प्रत्येक समापन अवधि के लिए प्रति तिमाही 1500/- रुपये का समापन भत्ता पाने का हकदार होगा।
- (8) 1 नवंबर, 2017 से, यदि एक दिन के कार्य घंटों को कम से कम दो घंटे के अंतराल पर विभाजित किया जाता है, तो एक अधिकारी प्रति माह 300/- रुपये की दर से विभाजित ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।
- (9) यदि किसी अधिकारी को छुट्टी के दिन तिजोरी या लॉकर के संरक्षक के रूप में काम करने की आवश्यकता होती है, तो वह उस दर पर दैनिक भत्ता पाने का पात्र होगा, जिस दर पर वह हकदार है।

- (10) 1 नवंबर, 2022 से, एक अधिकारी नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट पहाड़ी और ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्:—

तालिका

क्र.सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	1000 मीटर या उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मरकारा शहर	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 1450 रुपये प्रति माह के अधीन।
2.	1500 मीटर या उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 1900 रुपये प्रति माह के अधीन।
3.	3000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5 प्रतिशत, अधिकतम 3750 रुपये प्रति माह के अधीन।

- (11) 1 नवंबर, 2022 से, एक अधिकारी 850/- रुपये प्रति माह के शिक्षण भत्ते के साथ-साथ महंगाई भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

नोट: लागू महंगाई भत्ता सहित शिक्षण भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभों, अर्थात् पेंशन (परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन योजना), भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित) के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

- (12) 1 नवंबर, 2022 से, ऐसे अधिकारी जो शहर क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं, 1200/- रुपये प्रति माह के निश्चित स्थान भत्ते के लिए पात्र होंगे, जिसे महंगाई भत्ता, अधिवर्षिता लाभ, अर्थात् पेंशन जिसमें परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन योजना) शामिल है, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नहीं गिना जाएगा।
- (13) (a) वित्तीय वर्ष 2023-24 से, बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर, निम्नलिखित चयनित मापदंडों में से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन सभी अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा:

- (i) चालू खाता और बचत खाता;
- (ii) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ;
- (iii) विशेष उल्लेखित खाते;
- (iv) ब्याज-रहित आय
- (v) कुल कारोबार
- (vi) लाभप्रदता;
- (vii) परिसंपत्तियों पर प्रतिफल या इक्विटी पर प्रतिफल
- (viii) सरकारी योजनाएँ

(b) "प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा खंड (a) में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर, 0-15 (अधिकतम) दिनों के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के रूप में देय होगी।"

8. उक्त विनियमनों के विनियमन 24 में,—

(a) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद, एक अधिकारी स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकारी के स्वयं के प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र होगा कि उसने ऐसे व्यय किए हैं, जो नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट राशि के लिए दावा किए गए खातों के विवरण द्वारा समर्थित हैं, अर्थात्:—

तालिका

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	13000 रुपये प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, दोनों में से जो भी कम हो।
2.	वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	15400 रुपये प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, दोनों में से जो भी कम हो।

नोट 1: किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा भत्ते को जमा करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि यह राशि किसी भी समय ऊपर निर्धारित अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक न हो।

नोट 2: कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, चिकित्सा भत्ता योजना के तहत चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति दो महीनों— अर्थात् नवंबर, 2022 और दिसंबर, 2022—के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(b) उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(4) सभी अधिकारी आँखों की जाँच के लिए प्रति वर्ष 500/- रुपये की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।”

9. उक्त विनियमों के विनियमन 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, 1 नवंबर, 2022 से बैंक किसी अधिकारी को उसके वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर या आवास के मानक किराए, जो भी कम हो, के भुगतान पर आवासीय आवास प्रदान कर सकता है:

बशर्ते कि यदि अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, तो बैंक द्वारा उससे वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.075 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

इसके अलावा, यदि बैंक द्वारा ऐसा आवासीय आवास उपलब्ध कराया जाता है, तो बिजली, पानी, गैस और साफ-सफाई के शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

10. उक्त विनियमों के विनियम 31 में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

बशर्ते कि यदि स्वीकृति प्राधिकारी अधिकारी की छुट्टी अस्वीकार करता है या स्थगित करता है, तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

11. उक्त विनियमों के विनियम 32 में उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) 1 अप्रैल, 2024 से, एक अधिकारी वर्ष में चार बार आधे दिन के लिए दो दिन की आकस्मिक छुट्टी लेने का पात्र होगा, जिनमें से दो अवसर सुबह के होंगे और दो अवसर दोपहर के होंगे:

इस श्रेणी के अंतर्गत आकस्मिक अवकाश लेने के लिए चौबीस घंटे पहले आवेदन करना आवश्यक होगा:

बशर्ते कि आकस्मिक अवकाश के शेष को 'न लिए गए आकस्मिक अवकाश' खाते में ले जाते समय, यदि शेष में कोई भिन्न हो, तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

12. उक्त विनियमों के विनियमन 33 में,—

(a) उप-विनियमों (4) और (5) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:—

“(4) 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, विशेषाधिकार अवकाश को अधिकतम दो सौ सत्तर दिनों तक संचित किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ छुट्टी के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकृत कर दिया गया हो।

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण को अधिकतम 255 दिनों तक सीमित रखा जाएगा:

इसके अलावा, कोई भी अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्योहार के समय, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पाँच दिनों की दर से 'प्रिविलेज लीव' (विशेषाधिकार अवकाश) को नकदीकरण के भी पात्र होंगे; और जिस अधिकारी ने पहले ही 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर ली है, वह अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिनों की दर से 'विशेषाधिकार अवकाश' को नकदीकरण करने के पात्र होंगे।

(5) विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने के इच्छुक अधिकारी को सामान्यतः अवकाश किराया रियायत के उद्देश्य को छोड़कर, ऐसे अवकाश का लाभ उठाने के अपने इरादे की सूचना न्यूनतम दस दिन पहले देनी होगी।

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यपालक समिति के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने हेतु दस दिन की अग्रिम सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।”;

(b) उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(7) 1 अप्रैल, 2024 से, विशेषाधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजनों के लिए, आकस्मिक अवकाश और अनिवार्य अवकाश को छोड़कर, लिए गए सभी प्रकार के अवकाशों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।”

13. उक्त विनियमों के विनियम 34 में,—

(a) उप-विनियम (1) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से कोई अधिकारी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से रुग्ण अवकाश का पात्र होगा:

इसके अलावा, अधिकारी की संपूर्ण सेवा अवधि में कुल रुग्ण अवकाश (नियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त रुग्ण अवकाश सहित) सात सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगा।”;

(b) उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्:—

“(6) 1 अप्रैल, 2024 से, कोई भी एकल पुरुष कर्मचारी अपने आठ वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की बीमारी के लिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर, रुग्ण अवकाश ले सकता है।

(7) 1 अप्रैल, 2024 से, कोई भी महिला कर्मचारी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, हर महीने एक दिन की रुग्ण अवकाश ले सकती है।”

(8) 1 अप्रैल, 2024 से, कोई भी अधिकारी अपने 15 वर्ष या उससे कम उम्र के विशेष बच्चे की बीमारी के लिए, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिनों की रुग्ण अवकाश ले सकता है; इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ”

(9) 1 अप्रैल, 2024 से, 58 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के अधिकारी-कर्मचारी, अपने कार्यस्थल के अलावा किसी अन्य जगह पर अपने पति/ पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने पर, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की रुग्ण अवकाश ले सकते हैं।”

14. उक्त विनियमों के विनियम 36 में,—

(a) उप-विनियम (1) के खंड (a) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(a) कोई महिला अधिकारी कर्मचारी, किसी एक अवसर पर छह माह से अनधिक अवधि के लिए और अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान बारह माह के लिए, मूल वेतन पर प्रसूति अवकाश की पात्र होगी:

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में, मातृत्व अवकाश की अवधि आठ महीने होगी:

इसके अलावा, बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, एक ही बार में दो से अधिक बच्चों के जन्म के मामले में, मातृत्व अवकाश की अवधि बारह महीने होगी:

यह भी बशर्ते कि मातृत्व अवकाश को आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाकर लिया जा सकता है।”

(b) खंड (d) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(d) एक महिला अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवाकाल के दौरान एक बार, एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए, अधिकतम नौ माह की अवधि तक की छुट्टी ले सकती है; यह छुट्टी निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:—

(i) छुट्टी केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए ही दी जाएगी;

- (ii) बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया उचित कानूनी माध्यम से होनी चाहिए और कर्मचारी को ऐसी छुट्टी स्वीकृत करवाने के लिए बैंक के समक्ष गोद लेने का विलेख प्रस्तुत करना होगा;
- (iii) यह छुट्टी उन मामलों में जैविक माँ को भी उपलब्ध होगी जहाँ बच्चा सरोगेसी के माध्यम से जन्म लिया हो;
- (iv) यह छुट्टी संपूर्ण सेवाकाल के दौरान 12 माह की कुल पात्रता सीमा के भीतर ही ली जा सकेगी।”;

(c) खंड (e) के स्थान पर निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“(f) 1 अप्रैल, 2024 से, इन विट्रो फर्टिलिटी (आईवीएफ) उपचार के लिए मातृत्व अवकाश, बारह माह की समय सीमा के भीतर, चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर लिया जा सकेगा।

(g) 1 अप्रैल, 2024 से, किसी महिला कर्मचारी द्वारा शिशु के मृत जन्म अथवा जन्म के अट्टाईस दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु की स्थिति में साठ दिनों तक विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है।

15. उक्त विनियम के विनियम 37A के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“37A. विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश— (1) 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी, कोई अधिकारी उन अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश का पात्र होगा, जब वह जिस शाखा में कार्यरत है, या जिस स्थान पर वह निवास कर रहा है, वह कर्पूरु दंगों, निषेधाज्ञाओं, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और इसी तरह की अन्य स्थितियों से प्रभावित हो।”

(2) 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी, शारीरिक रूप से या अस्थि-दिव्यांगता से ग्रस्त अधिकारी चार दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी के हकदार होंगे।

(3) 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, अखिल भारतीय अधिकारी संघ या संगठन के मुख्य पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में पच्चीस दिनों तक की विशेष छुट्टी प्रदान की जाएगी।

(4) 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, जो अधिकारी विभागीय जाँच में रक्षा प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत अधिकारी, किसी अधिकारी कर्मचारी की रक्षा संबंधी प्रस्तुति तैयार करने के उद्देश्य से एक दिन का विशेष अवकाश ले सकते हैं:

बशर्ते कि इस प्रकार का विशेष अवकाश एक वर्ष में अधिकतम दस बार ही लिया जा सकेगा।

(5) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश तथा कोई विशेष अवकाश भी प्रदान किया जा सकता है, जिसका निर्णय बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।”

16. उक्त विनियमों के विनियम 37A के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“37B. शोक अवकाश.— किसी अधिकारी कर्मचारी को उसके परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता और सास-ससुर) के निधन पर, उतने दिनों का शोक अवकाश दिया जाएगा, जितने दिन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएं:

बशर्ते कि बीच में पड़ने वाली छुट्टियां शोक अवकाश का हिस्सा होंगी।

इसके अलावा, उक्त अवकाश मृत्यु के अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए।

साथ ही, विशेषाधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजन से उक्त अवकाश को "सक्रिय सेवा" नहीं माना जाएगा।

17. उक्त विनियमों के विनियम 41 में,—

(a) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) 1 अप्रैल, 2024 से, जहाँ कहीं भी किसी अधिकारी को ड्यूटी पर यात्रा करनी अपेक्षित हो, वहाँ निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्:—

(a) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का कोई अधिकारी, किसी भी ट्रेन से (प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी, शताब्दी, तेजस, वंदे भारत या अमृत भारत आदि सहित (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा:

बशर्ते कि यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक या जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाए तो ऐसा अधिकारी हवाई यात्रा (इकोनॉमी श्रेणी) कर सकता है;

(b) मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी खंड (a) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा:

बशर्ते कि यदि तय की जाने वाली दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो तो वह हवाई जहाज से (इकोनॉमी श्रेणी में) यात्रा कर सकता है:

इसके अलावा, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारोबारिक या जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाए तो वह कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज से (इकोनॉमी श्रेणी में) यात्रा कर सकता है;

(c) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का कोई अधिकारी किसी भी ट्रेन, जिसमें प्रीमियम ट्रेनों भी शामिल हैं [जैसा कि खंड (a) में उल्लिखित है], में एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार है;

(d) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का कोई अधिकारी उन स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकता है जो हवाई या रेल मार्ग से जुड़े नहीं हैं, बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो:

बशर्ते कि जब दो स्थानों के बीच की अधिकांश दूरी हवाई या रेल मार्ग से तय की जा सकती है, तो सामान्यतः शेष दूरी ही कार से तय की जानी चाहिए;

(e) सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किसी अन्य अधिकारी को अपने वाहन, टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

(f) किसी भी श्रेणी या वेतनमान का अधिकारी सड़क, हवाई या रेल मार्ग से असंबद्ध स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा;

(g) अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) में यात्रा के लिए किराए का हकदार होगा।

नोट 1: ट्रेन के किराए पर लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पात्रता के अतिरिक्त होगा।

नोट 2: प्रचलित गतिशील किराया प्रणाली को देखते हुए, बुकिंग की तिथि पर लगाए गए ट्रेन टिकट के प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी।;

(b) उप-विनियम (4) में खंड (a) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(a) ठहराव (हॉल्टिंग) भत्ता.— 1 अप्रैल, 2024 से तालिका के कॉलम (1) में निर्धारित श्रेणी या वेतनमान में कार्यरत अधिकारी, तालिका के कॉलम (2) में निर्धारित संबंधित दर पर दैनिक ठहराव भत्ते के हकदार होंगे, अर्थात्:—

तालिका

क्र.सं.	अधिकारियों की श्रेणी या वेतनमान	ठहराव भत्ता			
		मेट्रो रु.	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर रु.	क्षेत्र I रु.	अन्य स्थान रु.
(1)	(2)	(3)			
1.	वेतनमान VI और उससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
2.	वेतनमान IV और V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
3.	वेतनमान I, II और III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800:

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम परंतु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपरोक्त दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण - विराम भत्ते की गणना करने के प्रयोजन के लिए “प्रतिदिन” का तात्पर्य चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद के किसी भाग से होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम हो, वहां “प्रतिदिन” का तात्पर्य आठ घंटे से कम नहीं की अवधि से होगा।”

18. उक्त विनियमों के विनियम 42 में,—

- (a) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(3) 1 अप्रैल, 2024 से स्थानांतरित अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से संबंधित व्यय हेतु एकमुश्त राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:—

तालिका

क्र.सं.	श्रेणी या वेतनमान	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक (वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	रु.50000/-
2.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	रु.40000/-”;

(b) उप-विनियम (4) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, जहाँ बैंक द्वारा किसी अधिकारी को उसकी नई पोस्टिंग की स्थान पर रहने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, और जहाँ ऐसे अधिकारी को, अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से, कार्यभार संभालने की प्रक्रिया में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है, वहाँ सक्षम प्राधिकारी, ऐसे अधिकारी के नई जगह पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, मामले की मेरिट के आधार पर, पंद्रह दिनों की अवधि के लिए या जब तक उसे रहने के लिए क्वार्टर उपलब्ध नहीं हो जाते—इनमें से जो भी पहले हो—उसे या तो रहने और खाने का खर्च या ठहराव भत्ता देने पर विचार कर सकता है।”

19. उक्त विनियमों के विनियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“44 अवकाश यात्रा रियायत.—

(1) चार वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, कोई अधिकारी, दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार, अपने मूल निवास स्थान की यात्रा के लिए 'लीव ट्रेवल कंसेशन' (अवकाश यात्रा रियायत) का पात्र होगा:

बशर्ते कि वह दो वर्षों के एक ब्लॉक में अपने मूल निवास स्थान की यात्रा कर सकता है, और दो वर्षों के दूसरे ब्लॉक में, सबसे छोटे मार्ग से, भारत में किसी भी स्थान की यात्रा कर सकता है।

(2) 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, वैकल्पिक रूप से, कोई अधिकारी चार साल के ब्लॉक या दो साल के ब्लॉक (जैसा भी मामला हो) के दौरान किसी भी समय एक विकल्प का प्रयोग करके, अपनी 'अवकाश यात्रा रियायत' (एलटीसी) (निवास स्थान की यात्रा को छोड़कर) को समर्पण कर भुना सकता है; ऐसा करने पर वह टेन से यात्रा की उस श्रेणी के लिए पात्र किराए के बराबर राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसके लिए वह पात्र है—यह पात्रता कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारियों के लिए 5,500 किलोमीटर (एक तरफ़ा) की दूरी तक, और वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 6,500 किलोमीटर (एक तरफ़ा) की दूरी तक मान्य होगी:

बशर्ते कि अवकाश यात्रा रियायत को नकदीकरण कराने का विकल्प का चयन करने वाला अधिकारी, जिस अवधि में ऐसी रियायत का लाभ उठाया जाता है, उस दौरान केवल एक बार ही अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है, और अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय विशेषाधिकार अवकाश को भुनाने की सुविधा भी अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा का लाभ उठाते समय उपलब्ध होती है।

(3) जिस तरीके और श्रेणी के तहत कोई अधिकारी स्थानांतरण पर यात्रा करने के लिए अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, वह वही होगा जिसके तहत अधिकारी सामान्यतः यात्रा करने का हकदार होता है, और अन्य नियम व शर्तें जिनके अधीन कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, वे समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय की जाएंगी।

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय, हवाई यात्रा के लिए सबसे कम किराए वाली इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा करने के हकदार होंगे, जिसके लिए प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया या तय की गई दूरी के लिए लागू एसी प्रथम श्रेणी का किराया होगा, जो भी कम हो। यही नियम मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारियों पर भी लागू होंगे, जब वे अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाते हैं और दूरी 500 किलोमीटर से कम होती है।

(4) प्रत्येक चार वर्ष में एक बार, जब कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, तो उसे एक बार में तीस दिनों से अधिक की विशेषाधिकार छुट्टी का समर्पण करने और नकदीकरण कराने की अनुमति दी जा सकती है, या वह दो वर्षों के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर और दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करते समय, प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम पंद्रह दिनों या एक ब्लॉक में तीस दिनों तक विशेषाधिकार छुट्टी का नकदीकरण कराने की अनुमति दी जा सकती है, और छुट्टी

भुनाने के उद्देश्य से उस माह के लिए देय सभी पारिश्रमिक स्वीकार्य होंगे जिस माह के दौरान अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाया जाता है:

बशर्ते कि किसी अधिकारी को, अपनी इच्छा अनुसार, प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने के लिए एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी का नकदीकरण कराने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वह इस संबंध में बैंक को एक पत्र दे और बैंक को राशि कोष में भेजने के लिए अधिकृत करे।

- (5) जहां पति और पत्नी दोनों एक ही बैंक में काम करते हैं, वहां अवकाश यात्रा रियायत का लाभ अलग-अलग लिया जा सकता है।
- (6) पूर्वोत्तर राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, अवकाश यात्रा रियायत गुवाहाटी से शुरू होगा, और उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक का पात्र ट्रेन किराया उन्हें अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा।
- (7) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से चेन्नई या कोलकाता, लक्षद्वीप से कोच्चि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के दूर-दराज के इलाकों की शाखाओं, या किसी भी अन्य ऐसे क्षेत्र के लिए, जो सीधे ट्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है, वहां कार्यरत कर्मचारियों को 'अवकाश यात्रा रियायत' के तहत, उनके सामान्य अधिकार के अलावा, निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तक का किराया भी अतिरिक्त रूप से प्रतिपूर्ति किया जाएगा।
- (8) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ यात्रा पर जाने वाले सहयोगी (एस्कॉर्ट) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवकाश यात्रा रियायत सुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्:-
 - (a) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी;
 - (b) अधिकारी की शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि यात्रा के लिए एक एस्कॉर्ट (सहयोगी) की आवश्यकता हो, और किसी भी संदेह की स्थिति में, विभाग के प्रमुख या नियंत्रक का निर्णय अंतिम माना जाएगा;
 - (c) ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ जाने के लिए, उसका कोई वयस्क आश्रित पारिवारिक सदस्य न हो;
 - (d) ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी और उसके साथ जाने वाला व्यक्ति (एस्कॉर्ट), रेल या बस के किराए में मिलने वाली किसी भी छूट का लाभ उठाएंगे, जो ऐसे मामलों में रेलवे या राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरणों द्वारा दी जा सकती है; और
 - (e) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो एक आश्रित के रूप में 'अवकाश यात्रा रियायत' का हकदार है, वह ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ यात्रा पर न जाए।
- (9) जहाँ किसी अधिकारी ने अवकाश यात्रा रियायत या अग्रिम छुट्टी हेतु आवेदन किया हो और टिकट भी बुक कर लिए हो, और प्रबंधन द्वारा उस अवकाश यात्रा रियायत को अस्वीकार या स्थगित कर दिया जाए, तो टिकट रद्द करने का प्रभार बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा।
- (10) जहां किसी अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार "अवकाश यात्रा रियायत" या छुट्टी के लिए आवेदन किया है और उसे मंजूरी मिल गई है, और जब ट्रेन टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं है, तो 'तत्काल' या 'प्रीमियम तत्काल' के तहत खरीदे गए टिकटों का प्रतिपूर्ति किया जाएगा।"

20. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

“अनुसूची

[विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें]

1 नवंबर, 2022 से, कोई भी अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ता के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार इसे पूर्ण या आंशिक रूप से वापस नहीं ले लिया जाता या संशोधित नहीं कर दिया जाता, अर्थात्:—

तालिका
विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र.सं.	स्थान	भत्ते (रुपये में)	
		वेतन ₹48,481/- से कम	वेतन ₹48,481/- से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम		
	(a) चिम्पटुइपुई जिला और लुंगलेई जिले में लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र।	4100	5300
	(b) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला	4100	5300
	(c) संपूर्ण ऐजोल जिला	2700	3400
2.	नागालैंड	4100	5300
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
	(a) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह	4100	5300
	(b) दक्षिणी अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	4100	5300
4.	सिक्किम	4100	5300
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	4100	5300
6.	असम	1000	1200
7.	मेघालय	1000	1200
8.	त्रिपुरा		
	(a) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(b) त्रिपुरा के सभी दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर	2700	3400
9.	मणिपुर	2700	3400
10.	अरुणाचल प्रदेश		

	(a) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(b) अरुणाचल प्रदेश के सभी दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर	4100	5300
11.	A. जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश		
	(1) कठुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी	4100	5300
	(2) उधमपुर जिला:		
	(a) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमाग इलाका, ठाकराकोट और नागोटे	4100	5300
	(b) नीचे (c) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर माहौर तहसील के सभी क्षेत्र	4100	5300
	(c) मोहरे तहसील में कंबन की ओर से गोयल तक के क्षेत्र और केसी की ओर से अरनास तक के क्षेत्र	4100	5300
	(3) डोडा जिला: कश्मीर तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम का इलाका	4100	5300
	(4) बारामूला जिला:		
	(a) संपूर्ण गुरेज़-निराबत, तंगदार उप-विभाजन और केरन इलाका	4100	5300
	(b) मोटचिल	4100	5300
	(5) पुंछ और राजौरी जिला: पुंछ और राजौरी जिले के वे क्षेत्र जिनमें पुंछ और राजौरी तथा सुंदरबानी नगर और अन्य शहरी क्षेत्र शामिल नहीं हैं।	2700	3400
	(6) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (5) में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित हैं या ऐसे स्थान जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ता के लिए योग्य घोषित कर सकती है।	2700	3400
	B. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश: लेह जिला: नोयामा और नोब्रे ज़ांस्कर जिले के अन्य सभी स्थान	4100	5300
12.	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चम्बा जिला		
	(a) पांगी तहसील, भरमौर तहसील में निम्नलिखित पंचायतें और गाँव: पंचायतें: बड़गांव, बजोल, देवल कुगती, नयागाम और टुंडा गाँव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा के कनारसी	4100	5300
	(b) भरमौर तहसील, पंचायतों और गांवों को छोड़कर उपरोक्त (a) में शामिल है	4100	5300
	(c) भरतियात तहसील, चुराह तहसील, डलहौजी शहर में झंडरू पंचायत (बनीखेत सहित)	2700	3400
	(2) किन्नौर जिला		

(a) असरंग, चितकुल और हांगो कुनो या चारंग पंचायतें; 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नाथपा और रूपी की ग्राम पंचायतें शामिल हैं; पूह उप-विभाजन, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर	4100	5300
(b) (a) में ऊपर शामिल क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण जिला	4100	5300
(3) कुल्लू जिला		
(a) निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं	4100	5300
(b) बाहरी सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बुरो के गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला बाहरी सराज क्षेत्र और पंद्राबीस के परगना को छोड़कर, लेकिन तहसील निरमंड के जगत-खाना और बुराओ गांवों सहित)	2700	3400
(4) लाहौल और स्पीति जिला: लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	4100	5300
(5) शिमला जिला		
(a) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चंडी-ब्रांडा की पंचायतें शामिल हैं	4100	5300
(b) डोडरा-कावर तहसील, काशापथ तहसील के रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत और सराहन परगना के मुनीश, गोरी चैबीस	4100	5300
(c) (I) चौपाल तहसील (i) सराहन परगना के घोरी, पंजगांव, पाटसनौ, नौबीस और तीन कोटी; (ii) तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत; (iii) परगना बरबीस; और (iv) रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और गोरी नोग, (II) शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जटोग, कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू)	2700	3400
(6) कांगड़ा जिला:		
(a) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र	4100	5300

<p>(I) कांगड़ा ज़िले का धर्मशाला नगर तथा निम्नलिखित कार्यालय, जो नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित हैं, किंतु धर्मशाला नगर में शामिल हैं:</p> <p>(a) महिला आईटीआई, दारी, (b) मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, (c) बाल कल्याण और नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, सकोह, (d) निचले सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय (e) कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, (f) एचआरटीसी वर्कशॉप, सधेर, (g) आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, (h) वन निगम कार्यालय, शमनगर, (i) चाय फैक्ट्री, दारी, (j) आई.पी.एच. उपमंडल, दारी (k) निपटान कार्यालय, शामनगर, (l) बिनवा परियोजना, शामनगर,</p> <p>(II) पालमपुर नगर, जिसमें पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर तथा निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं, जो इसकी नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित हैं, किंतु पालमपुर नगर में सम्मिलित हैं:</p> <p>(a) एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय कैंपस, (b) पशु विकास कार्यालय या जर्सी फार्म, बनूरी,, (c) रेशम उत्पादन कार्यालय या भारत-जर्मन कृषि कार्यशाला या एचपीपीडब्ल्यूडी प्रभाग, बुंडला, (d) विद्युत उपमंडल, लोहना, (e) डी.पी.ओ. निगम, बुंडला, (f) इलेक्ट्रिकल एचपीएसई डिवीजन, घुग्गर</p>	2700	3400
(7) मंडी ज़िला:		
<p>जोगिंदरनगर तहसील की चुहार घाटी, थुनाग तहसील में पंचायतें: बगरा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गट्टू, गरियास, जंजैहली, जरयार, जोहार कल्हणी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचन, थाचधार, ताची, थाणा धरमपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें: बिंगा, कमलाह, सकलाना, तनयार और तारखोला, करसोग तहसील की पंचायतें- बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुड़ी, मंज, पेखी, सैज, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें- बोही, बटवारा, धन्यारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा</p>	2700	3400
<p>(8) सिरमौर जिला:</p> <p>(a) निम्नलिखित पंचायतें (i) बनी, बाखली (पच्छाद तहसील), (ii) भरोग भनेरी (पांवटा तहसील), (iii) बिड़ला (नाहन तहसील), (iv) डिब्बर (पच्छाद तहसील) और (v) थाना कसोगा (नाहन तहसील)</p> <p>(b) थांसगिरी क्षेत्र</p>	2700	3400

	(9) सोलन जिला: मांगल पंचायत	2700	3400
	(10) हिमाचल प्रदेश के वे शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं	1000	1200
13.	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4100	5300
14.	पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा के दक्षिण में), अर्थात्, भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलमथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रायदिघी, भांची, पत्थर प्रतिमा, भागबतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला और घुसीघटा (कुल्टी)	1000	1200.".

बी पी जाटव, मुख्य महाप्रबंधक
[ADVT.-III/4/Exty./47/2026-27]

नोट: केनरा बैंक (अधिकारियों) सेवा विनियम, 1979 भारत के राजपत्र में 14 अप्रैल, 1990 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किए गए, यथा:—

क्रम संख्या	राजपत्र अधिसूचना संख्या	सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	42	19.10.1996
2.	49	07.12.2002
3.	16	16.04.2011
4.	04	27.01.2018
5.	138	28.03.2020
6.	949	28.11.2024

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इन विनियमों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभाव में लाया गया है, ये इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंकिंग संघ और बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारियों के संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के नियम व शर्तों के अनुसार है। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

CANARA BANK
(Human Resources Wing)
NOTIFICATION

Bengaluru, the 17th April, 2026

F. No. HRW PM 257 2026.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Canara Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Canara Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Canara Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Canara Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

“(f) ‘family’, in relation to an Officer employee for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, means —

- (i) the spouse of the officer;
- (ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);
- (iii) wholly dependent physically or mentally challenged brothers or sisters with forty per cent. or more disability;
- (iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;
- (v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters; and
- (vi) parents wholly dependent on the officer:

Provided that in the case of physically or mentally challenged children, irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage subject to fulfilling the income criteria for dependent.

Explanation 1.—The expression “wholly dependent family member” shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs.18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs.18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs.18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

Explanation 2.— For the purposes of medical expenses reimbursement scheme and Leave Fare Concession, for all Officers, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered. The officer shall have

the choice to substitute either of the dependents or both once in a calendar year.

Explanation 3.— This definition shall be effective from the 1st April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme, the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1st November, 2024”.

3. In regulation 4 of the said regulations,—

(a) the *Explanation* to sub-regulation (7) shall be omitted;

(b) for sub-regulations (9) and (10), the following shall be substituted, namely:—

“(9) On and from the 1st November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VIII = Rs. 253000 - 9000/4 - 289000

Scale VII = Rs. 156500 - 4340/4 - 173860

Scale VI = Rs. 140500 - 4000/4 - 156500

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs. 120940 - 3360/2 - 127660 - 3680/2 - 135020

Scale IV = Rs. 102300 - 2980/4 - 114220 - 3360/2 - 120940

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs. 85920 - 2680/5 - 99320 - 2980/2 - 105280

Scale II = Rs. 64820 - 2340/1 - 67160 - 2680/10 - 93960

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs. 48480 - 2000/7 - 62480 - 2340/2 - 67160 - 2680/7 - 85920.

Explanation.— Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on the 1st November, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(10) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(11) On and from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I - III - 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV - V - 10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

- (12) On and from the 1st November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I - III - 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV - V - 19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VIII - 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon:

Provided that an Officer in Scale - VIII shall be eligible for special allowance on and from the 31st March, 2020.

- (13) On and from the 1st November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I - 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale II - III - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV - V - 30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VIII - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Note: The special allowance referred to in sub-regulations (11) to (13) with applicable dearness allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contributory Pension Scheme (National Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.”

4. In regulation 5 of the said regulations,—

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (9) of regulation 4, on and from the 1st November, 2022, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely:—

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (9) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;

- (c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for seven stagnation

increments, for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 2680/- each and the next five shall be of Rs. 2980/- each:

Provided that an officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (d) officers in Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments of Rs. 2980/- each for every two completed years of service:

Provided that an officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments for every two years of completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs. 2980/- each and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3360/- each:

Provided that an officer shall be eligible for seventh stagnation increment two years after release of sixth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of sixth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs. 3360/- each and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3680/- each:

Provided that an officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that an officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 4000/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that an officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that an officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (h) officers in Top Executive Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs. 4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs. 4340/- :

Provided that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs. 4000/- two years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs. 4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs. 4340/- six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (i) officers in Top Executive Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 4340/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later.

Note: The increment as mentioned in clauses (c) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation. — For the purposes of this sub-regulation, the grant of increments in the next higher scale shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as if they are in substantive posts.”;

(b) in sub-regulation (2),—

(i) before the *Explanation*, the following provisos shall be inserted, namely: —

“Provided that on and from the 1st November, 2022, the officers completing Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB) or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers examination (JAIIB) or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-I):

Provided further that the officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-II) shall be eligible for second additional increment from the 1st November, 2022 or the date of passing Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-II), whichever is later:

Provided also that in case where an officer, as on the 8th March, 2024, has already acquired or acquires Junior Associate of Indian Institute of Bankers (JAIIB) [Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-I)] or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) [Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-II)] after reaching maximum of the scale of pay [in case of JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II)], or after reaching the stage which is one stage less than maximum of scale of pay

[in case of CAIIB (CAIIB-II)], and has not earned increment, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years, as the case may be.”;

- (ii) in the *Explanation*, after clause (h) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

“(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the following Table, namely :—

Table

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of the Certified Associate of Indian Institute of Bankers.	(a) Rs1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale; (b) Rs.3425/- per month two years after reaching maximum of the Scale; and (c) Rs.5480/- per month three years after reaching maximum of the Scale:

Provided that an officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that on and from the 1st November, 2022, no Professional Qualification Pay shall be payable to an officer working in Scale VIII.”;

- (iii) in the Note, after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(vi) officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed Junior Associate of Indian Institute of Bankers (JAIIB) [Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-I)] or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) [Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-II)] and drawing Professional Qualification Pay-II shall be eligible for Professional Qualification

Pay-III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or from the 1st November 2022, whichever is later.

(vii) officers who have completed Junior Associate of Indian Institute of Bankers (JAIB) [Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIB-I)] or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIB) [Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIB-II)] and has reached the maximum in the scale of pay on or before the 1st November, 2022 and has not received the 1st stagnation increment on or before the 1st November, 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from the 1st November, 2022 and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay-I under this clause.”;

(c) in sub-regulation (3),—

(i) the Note after clause (g), shall be omitted;

(ii) after clause (h), the following shall be inserted, namely:—

“(i) On and from the 1st November, 2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

Table

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on the 1 st November, 2022 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669.

Note:

(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Table in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i)

of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the Table under clause (i) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned;
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.
- (iv) On and from the 1st day of November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in clause (c) of the *Explanation* to sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released as on the 1st November, 2000.

- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation, one year after reaching the maximum of the scale.”.

5. In regulation 21 of the said regulations,—

(a) the *Explanation* to sub-regulation (6) shall be omitted;

(b) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(8) On and from the 1st day of November, 2022,—

- (a) Dearness Allowance shall be payable at 1 per cent. of pay per percentage point of Index;
- (b) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base 2016=100. 0.01% change in Dearness Allowance on pay for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points;

- (c) the change in the Dearness Allowance rate shall be released on a quarterly basis on 1st May, 1st August, 1st November and 1st February based on the following, namely:—

Dearness Allowances release date	Quarterly average of Consumer Price Index points of the months	Applicable for the months
1 st May	January, February and March	May, June and July
1 st August	April, May and June	August, September and October
1 st November	July, August and September	November, December and January
1 st February	October, November and December	February, March and April;

- (d) there shall be no ceiling on Dearness Allowance;
 (e) while working out quarterly average, only first two decimals shall be considered.”.

Explanation.— for the purpose of this sub-regulation,-

- (a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including stagnation increment plus special allowance;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) to the *Explanation* in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.”.
6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st November, 2022,—

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:—

Table

Sl.No.	Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	10.0% of Pay
2.	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	9.0% of Pay
3.	Other places	8.0% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (3) of the above Table.

Note:- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.”.

7. For regulation 23 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st November, 2022, if an officer is serving in a place mentioned in column (2) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (3) thereof against that place shall be payable.

Table

Sl. No.	Places	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Places in Area 1 and above and in the State of Goa	Rs. 2300/- per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1900/- per month.

- (2) On and from the 1st November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (1) of the Schedule, Hill and Fuel Allowance as provided under sub-regulation (10) is

also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances, and not both.”;

Provided further that if such higher of the two allowances is less than the aggregate of Special Allowance and Hill and Fuel Allowance drawn by the Officer on the 31st December, 1989 then such difference shall be protected as Personal Allowance till such time the Officer remains at that place.

- (3) On and from the 1st November, 2017, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.600/- per month or Rs.525/- per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.
- (4) On and from the 1st April, 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.2500/- per month per child with a maximum upto two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year:

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st day of April, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank, where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month:

Provided further that where an officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major A class cities where the distance of such deputation is twenty kilometers and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as provided in sub-regulation (4) of regulation 41.

- (6) On and from the 1st April, 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 15 per cent. of his Basic Pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

- (7) On and from the 1st April, 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.
- (8) On and from the 1st November, 2017, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.300/- per month.
- (9) If an Officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem allowance at the rate to which he is entitled.
- (10) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the table below, namely:—

Table

Sl.No.	Place	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Place with an altitude of 1000 meters and above but less than 1500 meters and Mercara Town	2 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month
2.	Place with an altitude of 1500 meters and above but less than 3000 meters	2.5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month
3.	Place with an altitude of 3000 meters and above	5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month.

- (11) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs. 850/- per month along with Dearness Allowance thereon.

Note: The Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contributory Pension Scheme (National Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

- (12) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for a Fixed Location Allowance of Rs.1200/- per month, who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance, which shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits,

that is, pension including Defined Contributory Pension Scheme (National Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

(13) (a) From the financial year 2023-24, Performance Linked Incentive shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters:

- (i) Current Account and Savings Account;
- (ii) Non-Performing Assets;
- (iii) Special Mention Accounts;
- (iv) Non-Interest Income;
- (v) Total Business;
- (vi) Profitability;
- (vii) Return on Assets or Return on Equity;
- (viii) Government Schemes.

(b) The Performance Linked Incentive amount shall be payable in 0-15 (maximum) number of days of pay (Basic + Dearness Allowance) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a).”.

8. In regulation 24 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of own certificate of the officer of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely:—

Table

Sl.No.	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.13000/- per annum or the amount incurred, whichever is less.
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.15400/- per annum or the amount incurred, whichever is less.

Note 1: An officer may be allowed to accumulate unavailed medical allowance so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Note 2: For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical allowance scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2022 and December, 2022.”;

(b) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) All officers shall be eligible for reimbursement of Rs. 500/- per year towards eye check-up.”.

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), on and from the 1st November, 2022, it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075 per cent. of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 31 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where the Sanctioning Authority refuses or postpones the leave of the Officer, it shall record the reasons for the same in writing.”.

11. In regulation 32 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer shall be eligible to avail two days casual leave for half-a-day on four occasions in a year, out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon:

Provided that the casual leave under this category shall be availed after applying twenty-four hours in advance:

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.”.

12. In regulation 33 of the said regulations,—

- (a) for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely: —

“(4) On and from the 1st June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from the 1st April, 2024, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and fifty-five days:

Provided further that an officer shall also be eligible for encashment of Privilege Leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty-five years of age and above shall be eligible to encash Privilege Leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement.

- (5) An officer desiring to avail Privilege Leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention to avail such leave except for the purpose of Leave Fare concession:

Provided that on and from the 1st April, 2024, no such advance notice of ten days shall be required for availing Privilege Leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.”;

- (b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(7) On and from the 1st April, 2024, for the purposes of calculating Privilege Leave, all types of leave availed except casual leave and mandatory leave shall be excluded.”.

13. In regulation 34 of the said regulations,—

- (a) in sub-regulation (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that on and from the 1st April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave (including additional sick leave mentioned in regulation 35) shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.”;

- (b) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(6) On and from the 1st April, 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of eight years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1st April, 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate.

(8) On and from the 1st April, 2024, an officer may avail sick leave for the sickness of their special child of fifteen years age and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate.

(9) On and from the 1st April, 2024, officer employees of the age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalisation of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.”.

14. In regulation 36 of the said regulations,—

(a) for clause (a), in sub-regulation (1), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) A female officer employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that on and from the 1st April, 2024, in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months:

Provided also that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave.”;

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) A female officer employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
- (iv) the leave shall be availed within overall entitlement of 12 months during the entire period of service.”;

(c) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(f) On and from the 1st April, 2024, maternity leave may be availed for in vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months.

(g) On and from the 1st April, 2024, special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty-eight days of birth.”.

15. For regulation 37A of the said regulation, the following regulation shall be substituted namely:—

“37A. Special casual leave and special leaves.— (1) With effect from the 1st November, 2020, an officer shall be eligible for Special Casual Leave on occasions when the branch where the officer is working, or the place where he is residing, is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, and the like.

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days Special Casual Leave.

(3) With effect from the 1st April, 2024, the Principal Office bearers of All India Officers' Unions or Associations shall be granted Special Leave upto twenty-five days in a calendar year.

(4) With effect from the 1st April, 2024, officers who are defense representatives in departmental enquiry, may avail one day Special Leave for the purposes of preparing the defense submission of an officer employee:

Provided that such Special Leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

(5) An officer may also be granted Special Casual Leave and any Special Leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.”.

16. After regulation 37A of said regulations, the following regulation shall be inserted namely:—

“37B. Bereavement leave.— An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays will form part of the bereavement leave.

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of fifteen days of the demise.

Provided also that the said leave shall not be considered as “Active service” for the purpose of calculation of privilege leave.”.

17. In regulation 41 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st April, 2024, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

(a) an officer in Junior Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) an officer in Middle Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kilometers:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance, if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any train including premium trains [as mentioned in clause (a)] or by air (economy class);

(d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car;

(e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank’s vehicle;

- (f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail;
- (g) an officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

Note 1: Goods and Services Tax charges levied on train fare shall be over and above the entitlement.

Note 2: In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed.”;

- (b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) Halting Allowance.— On and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to *per diem* Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

Table

Sl.No.	Grades or Scales of officers	Halting Allowance			
		Metro Rs.	Major ‘A’ Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
(1)	(2)	(3)			
1.	Officers in Scale VI and above	4050	2925	2475	2150
2.	Officers in Scale IV and V	3375	2925	2475	2150
3.	Officers in Scale I, II and III	2925	2475	2150	1800:

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.— For the purpose of computing Halting allowance “*per diem*” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “*per diem*” shall mean a period of not less than eight hours.”.

18. In regulation 42 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the following Table, namely:—

Table

Sl.No.	Grade or Scale	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Senior Management and Top Executive (Officers in Scale IV and above)	Rs.50000/-
2.	Junior Management and Middle Management (Officers upto Scale III)	Rs.40000/-”;

(b) In sub-regulation (4), for the provisos the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that on and from the 1st April, 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an Officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either Lodging and Boarding charges or Halting Allowance for a period of fifteen days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.”.

19. For regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“44 Leave Travel Concession.—

(1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel Concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) With effect from the 1st April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometers (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III, and 6,500 kilometers (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

- (3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I, while availing Leave Travel Concession, shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled, whichever is less, and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession, where the distance is less than 500 kilometers.

- (4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding thirty days at a time or he may, while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the leave travel concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer, at his option, shall be permitted to encash one day additional Privilege Leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

- (5) Leave Travel concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.
- (6) For employees working in North-east States, Leave Travel concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.
- (7) The eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.

- (8) Leave Travel concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an officer with benchmark disabilities on the journey subject to following conditions, namely:—
- prior approval of the competent authority shall be obtained on each occasion;
 - the nature of physical disability of the officer shall be such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;
 - the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him;
 - the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the Rail or Bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and
 - any other person who is entitled to Leave Travel concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.
- (9) Where an officer has applied for Leave Travel concession or Leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Travel concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank.
- (10) Where an officer has applied for Leave Travel concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium tatkal shall be reimbursed.”.

20. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 23]

On and from the 1st day of November, 2022, an officer shall be eligible for Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified, either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:—

Table
Special Area Allowance

Sl. No.	Place	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs. 48,481/-	Pay above Rs. 48,481/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chimgtuipui district and areas beyond 25 kilometers from Lunglei Town in Lunglei district.	4100	5300

	(b) Entire Lunglei district excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town	4100	5300
	(c) Entire Aizawl district	2700	3400
2.	Nagaland	4100	5300
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, middle Andamans, little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4100	5300
	(b) South Andaman (including Port Blair)	4100	5300
4.	Sikkim	4100	5300
5.	Lakshadweep Islands	4100	5300
6.	Assam	1000	1200
7.	Meghalaya	1000	1200
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	4100	5300
	(b) Throughout Tripura except difficult areas	2700	3400
9.	Manipur	2700	3400
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4100	5300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas	4100	5300
11.	A. Union territory of Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4100	5300
	(2) Udampur District:		
	(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote	4100	5300
	(b) All areas in Mahore tehsil other than those included in (c) below	4100	5300
	(c) Areas upto Goel from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side in tehsil Mohre	4100	5300
	(3) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil	4100	5300
	(4) Baramulla District:		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar sub-division and Keran Illaqa	4100	5300
	(b) Matchill	4100	5300

	(5) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts	2700	3400
	(6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of eight kilometers from the Line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.	2700	3400
	B. Union territory of Ladakh: Leh District: Noyama and Nobre Zaskar All other places in the district	4100	5300
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Following Panchayats and villages in Bharmour Tehsil: Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4100	5300
	(b) Bharmour tehsil, excluding Panchayats and villages included in (a) above	4100	5300
	(c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat tehsil, Churah tehsil, Dalhousie town (including Banikhet proper)	2700	3400
	(2) Kinnaur District		
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats; 15/ 20 area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupj; Pooh sub-division, excluding the Panchayat areas specified above	4100	5300
	(b) Entire district other than areas included in (a) above	4100	5300
	(3) Kullu District		
	(a) 15/20 area of Nirmand tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4100	5300
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand tehsil) and entire district excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand)	2700	3400
	(4) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	4100	5300
	(5) Shimla District		

(a) 15/20 area of Rampur tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda	4100	5300
(b) Dodra-Kawar tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan	4100	5300
(c) (I) Chopal tehsil (i) Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan; (ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area; (iii) Pargana Barabis; and (iv) Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur tehsil, (II) Shimla town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu)	2700	3400
(6) Kangra District:		
(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	4100	5300
(I) Dharamshala town of Kangra district and the following offices located outside the municipal limits but included in Dharamshala town: (a) Women's ITI, Dari, (b) Mechanical Workshop, Ramnagar, (c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, (d) CRSF Office at lower Sakoh, (e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, (f) HRTC Workshop, Sadher, (g) Zonal Malaria Office, Dari, (h) Forest Corporation Office, Shamnagar, (i) Tea Factory, Dari, (j) I.P.H. sub- division, Dari (k) Settlement Office, Shamnagar, (l) Binwa Project, Shamnagar, (II) Palampur town, including Himanchal Pradesh Krishi Vishwa Vidyalaya campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur town : (a) H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, (b) Cattle Development Office or Jersey Farm, Banuri, (c) Sericulture Office or Indo-German Agriculture Workshop or HPPWD Division, Bundla, (d) Electrical sub-division, Lohna, (e) D.P.O. Corporation, Bundla, (f) Electrical HPSE division, Ghuggar	2700	3400

	(7) Mandi District:		
	Chhuhar valley of Jogindernagar tehsil, Panchayats in Thunag tehsil: Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gadoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana Following Panchayats of Dharampur Block: Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog tehsil - Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil - Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja	2700	3400
	(8) Sirmaur District: (a) Following Panchayats of (i) Bani, Bakhali (Pachhad tehsil), (ii) Bharog Bheneri (Paonta tehsil), (iii) Birla (Nahan tehsil), (iv) Dibber (Pachhad tehsil) and (v) Thana Kasoga (Nahan tehsil) (b) Thansgiri Tract	2700	3400
	(9) Solan District: Mangal Panchayat.	2700	3400
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above	1000	1200
13.	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat districts	4100	5300
14.	West Bengal: South 24 Parganas District Sunderban areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingaljanj, Basanti, Kuemari, Kultola and Ghushighata (Kulti)	1000	1200.”.

B P JATAV, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./47/2026-27]

Note: The Canara Bank (Officers') Service Regulations, 1979 were published in the Gazette of India on the 14th April, 1990 and subsequently amended *vide* the following notification published in the Gazette of India, Part III, Section 4, namely:—

Serial number	Gazette notification number	Date of publication in the official Gazette
1.	42	19.10.1996
2.	49	07.12.2002
3.	16	16.04.2011
4.	04	27.01.2018
5.	138	28.03.2020
6.	949	28.11.2024

EXPLANATORY MEMORANDUM

These Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.